Commission would be laid before the Parliament after completion of the formalities like translating the same into Hindi and also getting the copies made thereof both in English and in Hindi. The Eeport is under consideration of the Government.

टेलिफोन विभाग में दुर्विनियोग के संबंध में समाचार

1377. **श्री प्यारेलाल खंडेलवाल** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भोपाल से प्रकाशित 11 जून, 1984 को साप्ताहिक "चरैवैति" में "टेलीफोन विभाग में करोड़ों का गबन" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है और क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ; और

(ग) यदि अभी तक कोई जांच नहीं की गई है तो क्या सरकार जांच कराने का विचार रखती है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) से (ग) यह समाचार 11 से 17 जून, 1984 के "चरैवैति" साप्ताहिक संस्करण में ही जिसका केवल भोपाल से प्रकाशित किया जाता है, मिल सकता है। इंदौर टेलीफोन के टेलीफोन राजस्व बिंग में धोखाधड़ी का मामला जानकारी में आया था। इस मामले में विभागीय जांच की गई थी और यह मामला सी०बी०आई० में दर्ज करा दिया गया है।

आकाशवाणी केन्द्रों के समाचार एककों का दर्जा बढ़ाया जाना

1378. **श्री प्यारे लाल खंडेलवाल** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में लखनऊ और जयपुर आकाशवाणी केन्द्रों के समाचार एककों का दर्जा बढ़ाया गया है और वहां सम्पादक के पदों का सृजन किया गया है ;

(ख) क्या सरकार भोपाल आकाशवाणी केंद्र में एक समाचार सम्पादक नियुक्त करने का विचार रखती है ; और

(ग) यदि हां, तो यह नियुक्ति कब तक हो जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत): (क) नवम्बर, 1982 में आकाशवाणी में जयपुर और लखनऊ में सहायक समाचार सम्पादक का एक-एक पद जिसका वेतनमान 700-1300 रु० था, उन पदों में से था जिनका दर्जा बढ़ाकर 1100-1600 रु० के वेतनमान में समाचार सम्पादक के स्तर का कर दिया गया था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विभागेतर डाक कर्मचारियों की समस्याओं तथा सेवा शर्तों की जांच हेतु समिति

1379. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विभागेतर डाक कर्मचारियों की समस्याओं और सेवा शर्तों पर विचार करने के लिए संसद-सदस्यों और विशेषज्ञों की एक समिति गठित करने का विचार रखती है !

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर ना हो, तो इसके क्या कारण हैं ?